>

Title: Regarding Suprement Court's observation on free distribution of foodgrains among the poor in the country.

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती सुषमा स्वराज, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और स्वास्थ्य मंत्री जी से क्षमा मांगती हूं कि जिस बिल पर चर्चा हो रही है, उसे थोड़ी देर के लिए रोकते हुए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार सदन को देना चाहती हूं। पता नहीं मेरे साथियों ने अभी-अभी टेलीविजन पर देखा है या नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए यह कहा है कि एक तरफ इस देश में लोग भूखों मर रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों लाख टन अनाज गोदामों में पड़ा सड़ रहा है। इसलिए भूखों को, गरीबों को मुफ्त में यह अनाज बांटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए यह कहा है कि यह बात हमने सुझाव के तौर पर नहीं कही थी, हमने आदेश के तौर पर कही थी। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है। आज संसद के इस सत्र का आखिरी दिन है। मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने इसे सुझाव के तौर पर क्यों माना था। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ही दिया था। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की पालना सरकार करेगी, यह आश्वासन आज ही सदन में कृषि मंत्री जी के द्वारा आना चाहिए और एक सप्ताह के अंदर सरकार योजना बनाकर लाए कि किस तरह से निशुल्क यह अनाज गरीबों में बांटा जाएगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह शून्य काल नहीं है।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसलिए ऐसी योजना एक सप्ताह के अंदर सरकार लाए और ऐसा आश्वासन सदन में दे कि बिना पैसे के अनाज गरीबों और भूखों में बांटा जाएगा। सुबह भी हरसिमरत कौर जी ने यह मामला सदन में उठाया था, वह इससे जुड़ा हुआ है। देश में 40 लाख टन अनाज बेकार पड़ा सड़ रहा है।...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): इन्हें अगर बीच में सुना है तो हमें भी सुना जाए और सबको मौका दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने लिखित में अनुमति मांगी थी, क्या आपने लिखित में दिया है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। आप शून्य काल में उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): उपाध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष जी, सभी को बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): मेरा निवेदन है कि बिल अभी शुरू हुआ है, बिल पर डिस्कशन करना है तो करिये, नहीं करना है तो इसे पास कीजिए और उसके बाद पूरा डिस्कशन कर लीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको हमें भी सुनना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : बिल के बीच में कैसे होगा?...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): ये भेदभाव नहीं चलेगा। एक नेता ये खड़े हैं, दूसरे नेता ये खड़े हैं, इनकी बात भी आपको सुननी पड़ेगी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी लोग बैठ जाइये। ठीक है, सभी नेता दो-दो मिनट बोलेंगे। श्री शरद यादव जी आप बोलिये।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, बिल पर बहस हो रही थी, विकट परिस्थिति है, नेता विपक्ष ने इसमें इंटरवीन किया। पूरा देश इस समय महंगाई और भूख से पीड़ित है। मैं कह रहा हूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका अभी जो फैसला आया है, उसमें साफ कहा है कि हमारा जो पहला फैसला था वह आदेश था। इस देश के चार-पांच सूबों में अभी सूखा पड़ा है, सरकार कोई रास्ता निकाल करके, जो अनाज सड़ रहा है उसे बांटने का काम करे। एनडीए की सरकार में हमने पहले यह काम किया है। राजस्थान में हमने एक लाख टन अनाज फ्री में दिया था, यह कोई ऐसी नयी बात नहीं है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर तत्काल

कोई कार्रवाई करके, जिन इलाकों में सूखा है, वहां अनाज पहुंचाने का कार्य करना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अनाज सड़ रहा है, सुप्रीम-कोर्ट का फैसला ही नहीं आदेश है। इसलिए हम कह रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री जी सुन लें कि जब हमारी सरकार यूपी में थी और जब उस समय बाढ़ आई थी तो सारे कोल्ड-स्टोरेज हमने मालिकों से कहकर खुलवा दिये थे और कहा था कि लोगों को आलू दीजिए, हम आपका जितना पैसा बनेगा दे देंगे। इसके साथ-साथ हम वहां खुद गये और लोगों ने कहा कि इतना फायदा हमें कभी नहीं मिला। हमने वहां टेंट लगवा दिये थे और उन लोगों के साथ खाना खाया। अब क्या इंसानियत बिल्कुल चली गयी है, हम यहां क्यों आये हैं, हमें उसी जनता ने भेजा है।

गेहूं है और सड़ भी रहा है। बहुत अधिक मात्रा में चावल भी हुआ था, लेकिन सरकार ने खरीदा नहीं। किसान को बहुत सस्ता धान बेचना पड़ा। देश में सूखे का प्रकोप और बाढ़ का प्रकोप भी है। आप उस अन्न को गरीबों में बंटवाने की व्यवस्था कीजिए। हमने अपने समय में बंटवा कर दिखा दिया था। हिंदुस्तान में भूख के कारण डेढ़ लाख लोग मर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : इससे ज्यादा सरकार के लिए शर्म की क्या बात हो सकती है कि गल्ला होने के बावजूद भी, अनाज भरपूर पैदा होने के बावजूद भी लोग भूख से मर रहे हैं। साठ सालों के अंदर पांच लाख से ज्यादा लोग भूख से मरे हैं। महोदय, बकायदा अन्न और चावल गरीबों में बंटवाया जाना चाहिए। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। बहुत ज्यादा पैसा यात्राओं पर खर्च किया जाता है, लेकिन लोगों को मुफ्त में अन्न न देकर उन्हें भूख से मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हरसिमरत कौर जी, आप बैठ जाएं। आप सदन में इस तरह से चावल दिखा नहीं सकती हैं।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह तरीका गलत है। आप बैठ जाएं।

â€¦(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, कई बार हाउस में इस मामले को लेकर चर्चा हो चुकी है। पूरे देश में किसान, गरीब, मजदूर हैं, वे बाढ़ और सूखे से परेशान हैं। किसान भूखे मर रहे हैं। सदन में इस विषय पर चर्चा हुई कि गोदाम के बाहर अनाज सड़ रहा है। सरकार को इस अनाज को गरीबों में बंटवाना चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे नोटिस में लिया है। एक बार नहीं, दो बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा निदेश देने के बाद सरकार द्वारा इसका संज्ञान न लेने का क्या कारण है? यह बहुत गंभीर मामला है। अगर किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट का निदेश आता है, तो सरकार उसे नोटिस में लेती है। सुप्रीम कोर्ट गरीबों के, किसानों के पक्ष में फैसला देती है, तो केंद्र सरकार उसे नोटिस में नहीं लेती है। यह बहुत गंभीर मामला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो अनाज सड़ रहा है, उसे गरीबों में बंटवाना चाहिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाएं और माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY : Your Leader has already spoken on the subject. Why do you want to raise the issue again? ...(*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, we also share the concern expressed by other hon. Members on this issue. ...(*Interruptions*) The godown facilities are very poor. The Food Corporation of India (FCI) is not in a position to preserve the food grains properly. They are wasting them. Hence, the Supreme Court has directed the Government that the food grains could be given to the poor people instead of wasting the same. This is a welcome suggestion as the farmers are not able to get a remunerative price. It is high time when harvest is taking place throughout the country.

Therefore, the FCI should come forward to procure rice, wheat and other products. At the same time, whatever is there in the godowns has to be given free to the labourers and other poor people. This is very important. I request the Government to concede this request. ...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाएं।

â€¦(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY : Everybody wants to speak on every issue. ...(*Interruptions*) Do you not want the Minister to respond? ...(*Interruptions*)

Shri Ananth Kumar, every time you disturb the proceedings of the House. ...(*Interruptions*) It is becoming your habit. ...(*Interruptions*) Unfortunately, you raise the issue, and you do not want the Minister to respond. ...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाएं और सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: आप सब बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्मम): उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना गंभीर विषय है।...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : In a minute, they raise the matter and they want the Minister to be present here. ...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी आप सब लोग बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: It is very unfortunate that this is the attitude of the BJP. â€¦ (*Interruptions*)

श्री पवन कुमार बंसल: सर, ये लोग पार्लियामेंट का मखौल बना रहे हैं।...(व्यवधान) They are making a mockery of the Parliament. क्या मंत्री एक मिनट में हाजिर हो जाएंगे? सर, इन बातों का इन्होंने मखौल बना लिया है।...(व्यवधान) एक सैकेंड में बात करते हैं और उसके बाद सभी खड़े होकर शोर मचाते हैं।...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी केवल शोर मचाना चाहती है, इसके अलावा बात करना नहीं चाहती।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :आप लोग बैठ जाइए। कृपया आप सब शांत रहिए। मंत्री जी की बात सुनिए। क्या हाउस नहीं चलाना है? आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: Without giving a proper notice, everybody wants to speak. Leaders of every political party want to speak. Are there no rules?

श्री लालू प्रसाद (सारण): उपाध्यक्ष महोदय, गरीबों को मुफ्त में अनाज भिजवाइए। बिहार, यू.पी. और पंजाब में भी भिजवाइए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। बैठ जाइए। आपकी बात हो गयी। आपने अपनी बात कह दी। मंत्री जी खड़े हैं। अब उनको बोलने दीजिए। आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this issue has been agitating the minds of the people not only today, but for quite a long time. The hon. Supreme Court of India has given its direction much earlier. The hon. Minister of Agriculture has already stated the Government would not distribute it free. This is something unheard of. Today, with the hon. Supreme Court's order, the matter has become very clear. When you do not have enough storage facility and the food grains are getting rotten in the open, then why should the Government behave in this manner? Why should they not abide by the direction of the hon. Supreme Court? They should immediately distribute those food grains.

I think the Government stands on prestige and it wants a confrontation with the Supreme Court. This is very bad. They should immediately take steps and issue the food grains to the eligible persons.

â€¦(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : महोदय, हाउस में इस बारे में बहुत बार चर्चा हुई है। प्रश्न सं. 293 के उत्तर में कहा गया है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप विÂषय के बारे में दो मिनट में बोलिए। यह डिसकशन नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : मैं इसी के बारे में बोल रहा हूं। 300 लाख टन स्टॉक के बारे में सरकार का उत्तर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है लेकिन गवर्नमेंट सो रही है। ...(व्यवधान) हाउस में चर्चा होने के बाद भी, गवर्नमेंट के सामने कितनी बार चर्चा होने के बाद भी गवर्नमेंट ख्याल नहीं कर रही है। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट

का ऑर्डर हुआ है, उसके अनुसार तुंत पालन करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप डाटा मत दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : जो सरप्लस स्टॉक 600 लाख टन का है, इसे तुंत गरीब लोगों में बांट दीजिए। इसे एक दिन भी लेट मत कीजिए। आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कम से कम गवर्नमेंट आंख तो खोले और तुंत गरीब लोगों को बांटे। आंध्र प्रदेश में गेहूं की बहुत प्रॉब्लम है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। अजनाला जी आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए ताकत दी है। हमारा मसला है कि हिन्दुस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अनाज गरीबों में बांट दो लेकिन सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे रही है। हमारा यही मसला है कि सरकार जवाब दे और अनाज खराब हो रहा है, उसे भेजे। हमारा यही मसला है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपके नेता ने बोल लिया है अब आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लालू जी के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइए। आपके नेता ने बोल लिया है।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। लालू जी बोल रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

14.45 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

MR. CHAIRMAN : I request all the hon. Members to cooperate. It is a sensitive issue which we are discussing. Many hon. Members have expressed their views. Now, two hon. Members are left out – Shri Lalu and Shri Acharia. After that, the hon. Minister will reply. Please cooperate with the Chair.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please cooperate; we will finish this issue.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let us finish this issue.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let him finish this; after that, we will take it up. Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

MR. CHAIRMAN: This is the last day of this Session. Please cooperate, if we want to run the House. If every Member is taking this kind of attitude, we cannot do it. Please cooperate with the Chair. Shri Lalu, please continue.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Please cooperate with the Chair.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: First let him speak. Let us first solve this issue. Please cooperate with the Chair. All the Members cannot be given a chance. Only three hon. Members will be given a chance. After that, the hon. Minister will reply.

...(*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति महोदय, देश में प्रचुर मात्रा में गेहूं, चावल या अन्य अनाजों का संग्रह किया गया है, उनका उचित रख-रखाव न होने के कारण वह सड़ रहा है। इसके बारे में सदन के सभी माननीय सदस्यों और विशेषकर पंजाब से अकाली दल के माननीय सदस्यों ने चिन्ता जतलाई है। पंजाब के माननीय सदस्यों ने जो कुछ देखा, उसके बारे में जिक्र भी किया है। हम लोगों को अनाज को बर्बाद नहीं होने देना चाहिये। यह देश का और देश के गरीबों का सवाल है। जहां सूखा पड़ा हुआ है या बाढ़ आयी है, वहां लोग भूख के मारे तबाही के कगार पर हैं। न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब बल्कि प.बंगाल राज्य तक प्रभावित हैं। ..(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him. If you are serious, please listen to him.

...(*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद : देशभर के कई राज्य प्रभावित हो रहे हैं। इसमें राजनीति की बात नही हो रही है। यह न केवल सरकार की बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। यह सवाल माननीय कृषि मंत्री जी के सामने उठा था लेकिन उन्होंने इस मामले को हल्के-फुल्के ढंग से लेकर टाल दिया। विवश होकर यह बात सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अनाज गोदामों में सड़ रहा है, वह देशभर के गरीबो में फ्री बांटें यानी बांटने का आदेश दिया है...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Lalu, please address the Chair.

इसमें एक-दूसरे पर अंगुली उठाने का सवाल नहीं है। हम जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, आज वे इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लिए नून-रोटी का इंतजाम होगा या नहीं होगा।

महोदय, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हालत और पंजाब जहां से माननीय सदस्य आते हैं। You have already said all this.

...(*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद : आप हमें अपनी बात बोलने दीजिये। हम चाहते हैं कि आदेश का अनुपालन हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो है ही, ऊपर भगवान नीचे सुप्रीम कोर्ट और फिर संसद। यह संसद का आदेश है, साथ-साथ संसद का मैनडेट है, सरकार इसे मजाक में न ले। सारा गेहूं, चावल निकालकर गरीबों को बांटो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, हटो। यह हमारा सवाल है।...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, it is a matter of grave concern that one-fourth of the population goes to bed empty stomach.

MR. CHAIRMAN: We are discussing a serious matter. Please do not disturb.

SHRI BASU DEB ACHARIA : India is positioned among the 80 countries where the largest number of starvation death is 68....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Acharia Ji, come to the point directly. Do not go into the details. Do not take too much of the time of the House. You may briefly tell what do you want.

SHRI BASU DEB ACHARIA : When such a situation is prevailing in our country the food grains are rotting. A large quantity of food grains is kept in godowns. When there was a discussion in this House, we also demanded that the food grains should be distributed and universalized Public Distribution System should be introduced in our country. Subsidised food grains should be provided to the people.

MR. CHAIRMAN: Do not go into the details. You may talk about the rotting food grains.

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Supreme Court has directed this Government, it is rather a mandate, to distribute the food grains. Instead of allowing the food grains to rot, the Government should distribute food grains among the poor and the hungry people free of cost. This is our demand.

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): महोदय, देश भर में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम हैं, उन गोदामों की हालत सारे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने बतायी है। इसके लिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करने का कार्य मंत्री जी करेंगे। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आज भी कई गरीबों की बस्ती उजड़ रही है, उनके पास खाने का अनाज नहीं है। कई जगह बाढ़ आयी है। जैसे लेह में आपत्ति आयी, महाराष्ट्र में कई जगह आपत्ति आयी, छत्तीसगढ़ में आयी और इसके पहले भी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान बहुत जगह बाढ़ आ गयी, आपत्ति आ गयी। वहां यह दिया जाना चाहिए। मैं शिव सेना की ओर से आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा। माननीय शरद पवार साहब ने एक बार कहा था।...(व्यवधान)

महोदय, मैं यह डिमांड करना चाहता हूं कि एक तो पंजाब का जो 40 लाख टन चावल सड़ रहा है, वह सरकार को लेना चाहिए।...(व्यवधान) मैं यह भी कहूंगा कि माननीय शरद पवार साहब ने यह कहा था कि जिन ऑफिसर्स ने नेग्लिजेंसी की है, देखभाल नहीं की है, उन ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे? यह सारा अनाज गरीबों को मुफ्त दीजिये, फ्री दीजिये, यह मेरी डिमांड है।...(व्यवधान)

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): महोदय, मैं बहुत गंभीर विषय की ओर सारे सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी स्थिति, संसद की स्थिति इतनी शर्मनाक हो गयी है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हमें काम करना पड़ता है। यह सबसे ज्यादा दुखदायी और शर्मनाक स्थिति है।...(व्यवधान) जो काम हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत के करने का था, वह काम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर करेंगे। जनता में भी यही संदेश जा रहा है कि इस देश को सुप्रीम कोर्ट चला रही है, संसद नहीं चला रही है। यह मेरा नम्बर एक प्वाइंट है।

दूसरी बात यह है कि मैं और श्रीमती बादल, हम दोनों पिछले छः महीने से फूड कमेटी के सदस्य हैं। मैं सरकार की बात क्या बताऊँ, सरकार तो फेल हो ही रही है, लेकिन उसके फेल होने का कारण लालफीताशाही है, ब्यूरोक्रेसी है। जितने अधिकारी आते हैं, उनसे बार-बार श्रीमती बादल ने अपने प्रदेश की बात उठाई। कमेटी बनती रही और अब नई फसल आने को तैयार है। ...(व्यवधान) चावल सारे पंजाब के घरों में खाया जा रहा है, जिन घरों में खाया नहीं जाता था। ...(व्यवधान) उसमें क्या दिक्कत आई? ...(व्यवधान) उस चावल को बाँटने को कहते हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the Minister's speech.

*(Interruptions) â€¦ **

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Mr. Chairman, Sir, I have heard about this from television.

श्री लालू प्रसाद : हिन्दी में बोलिये।

श्री शरद पवार : मुझे टेलीविज़न पर रिपोर्ट देखने को मिली और कुछ प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि भी मुझे मिले। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अनाज के बँटवारे के बारे में, गोदाम कंस्ट्रक्शन के बारे में, पावर्टी लाइन के बारे में, एपीएल कैटागरी के बारे में कुछ डिसीज़न दिए, सुझाव दिए, ऑब्ज़र्वेशन किये, इस तरह की अलग अलग बातें मुझे यहाँ बतलाई गई। मैंने तुंत अपने दफ्तर में जाकर इसके फाइनल ऑर्डर जो कोर्ट ने दिये हैं, वह कलैक्ट करने की कोशिश की मगर अभी तक मेरे पास कोर्ट का फाइनल आर्डर नहीं आया है। मैं सदन को कहना चाहता हूँ कि यह सरकार सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इनके कोई भी डिसीज़न हों, इनकी पूरी तरह से इज्ज़त करेगी। इसके साथ-साथ इस संसद के माननीय सदस्यों ने इस संबंध में जो कुछ सुझाव दिये हैं उन पर भी सरकार गंभीरता से ध्यान देगी और यह दोनों तय कर इस पर जो कदम उठाने की आवश्यकता है, वह कदम उठाने की तैयारी इस सरकार की रहेगी, मगर ...(व्यवधान) But without reading the authentic

order, it will be improper on my part to brief this House as anybody can claim that I have misled the House which I do not want. That is why, I am going in depth and then I will submit...(*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद : संसद की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **